रविवारीय

आचार्य गौरव शर्मा, शिमला

कॉंग्रेस नेता राहुल गाँधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं . उनके द्वारा अब तक उछाले गये आरोपों में कोई भी प्रमाणित नहीं हो सका लेकिन इतिहास की कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो कॉंग्रेस को ही चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने के कटघरे में खड़ा करती हैं . श्री राहुल गाँधी द्वारा चुनाव आयोग पर की गई पत्रकार वार्ता का उत्तर केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पत्रकार वार्ता में ही दिया . उन्होंने पहला उदाहरण बाबा साहब अंबेडकर के चुनाव हारने का दिया और बताया कि अंबेडकर जी केवल 14561 वोटों से चुनाव हारे जबकि इस चुनाव में 74,333 वोट निरस्त किए गए थे . इसके विरुद्ध आंबेडकर जी ने 18 पन्नों की याचिका भी लगाई . इतने वोटों का निरस्त होना सामान्य घटना नहीं है यह चुनाव आयुक्त की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न उपस्थित करती है . एक अन्य घटना 1971 में श्रीमती इंदिरा गाँधी के रायबरेली से शासकीय साधनों का दुरूपयोग करके लोकसभा चुनाव जीतने की है . न्यायालय ने आरोप प्रमाणित माने और चुनाव को निरस्त कर दिया था .

मतदाता सूचियों की जांच का विरोध और चुनाव आयोग पर हमले के मायने

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी और इंडी गठबंधन के सदस्य दल विहार में मतदाता सूची के सत्यापन का तो विरोध कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग पर फर्जी मतदाता बनाने का आरोप लगाकर सड़क से लेकर संसद तक देश में नया तनाव पैदा रहे हैं. यह ठीक वही शैली है जो पाकिस्तान में इमरान खान और बंगलादेश में खालिदा जिया के विरुद्ध अपनाई गई थी. यह आँदोलन ऐसे समय तीव्र हुआ जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ हमला बोला.

विदेशी षड्यंत्र का उत्तर तो भारत दे देगा. यह वही अमेरिका है जिसने अटलजी के समय भारत द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाये थे. लेकिन भारत अपनी गति से आगे बढ़ता रहा. इस बार भी अमेरिका के टैरिफ हमले से भारत अपेक्षाकृत अधिक सक्षम होकर निकलेगा. लेकिन भारत को सदैव समस्या आन्तरिक तत्वों से रही. इन्हें आधुनिक शब्दावली में स्लीपर सेल कहते हैं. यह स्वयं सामने नहीं आते लेकिन भारत में भारत के ही चेहरों को अपना मोहरा बनाते हैं, इसी से विदेशी षड्यंत्र कारी सफल हुये हैं. वर्तमान समय में मतदाता सूची के बहाने उत्पन्न किये जा रहे राजनैतिक तनाव से भी कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो किसी षड्यंत्र की ओर संकेत कर रहे हैं. इस आँदोलन में तीन प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं जिनपर देश के प्रबुद्ध जनों को विचार करना आवश्यक है. पहली तो कॉंग्रेस और इंडी गठबंधन बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन रोकने केलिये पूरी शक्ति लगा रहा है. आशंका है इन प्राँतों में कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिये मतदाता बन गये हैं. जिनकी

जांच चल रही है. इसे रोकने केलिये उच्चतम न्यायालय का दरबाजा भी खटखटाया गया है. लेकिन दूसरी ओर केवल मीडिया के सामने मतदाता सूची को मुद्दा बनाकर एक धुंध फैलाई जा रही है. फर्जी मतदाता के बहाने कुछ नाम उछाले गये हैं, दो महिलाओं के नाम लिये गये, बनारस में एक सूची भी दिखाई गई. ये नाम सब हिन्दुओं के हैं. कॉंग्रेस द्वारा प्रचारित सूची में किसी ऐसी बस्ती का नाम नहीं है जो मुस्लिम बाहुल्य हो. तीसरा प्रश्न इस आँदोलन का समय है. कॉंग्रेस ने आठ अगस्त से बहुत तेजी दिखाई. पहले प्रेजेंटेशन दिया, फिर सांसद सड़क पर निकले. नौ अगस्त रक्षाबंधन का दिन था. रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक सनातन त्यौहारों का एक क्रम रहता है. लेकिन कॉंग्रेस ने पूरे देश का ध्यान त्यौहारों से हटाकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग की ओर खींचा. जिस दिन कॉंग्रेस और उनके साथी भारत की सड़क पर आँदोलन कर रहे थे उन्हीं दिनों पाकिस्तान की ओर से रक्षामंत्री मुनीर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे. इस बार मुनीर की धमकी ऐसे समय आई जब एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के बहाने भारत को धमका रहे थे और दूसरी ओर भारत की सड़कों पर यह आँदोलन इतना तीव्र था कि जन सामान्य का ध्यान अमेरिका और पाकिस्तान की धमकी से हटकर केवल आँदोलन से उत्पन्न तनाव में ही लग गया.

इन दिनों पूरी दुनियाँ के कुछ भागों में सत्ता हथियाने की एक नई शैली विकसित हुई है. इसमें सकारात्मक मुद्दों के आधार पर जन सामान्य में अपना समर्थन नहीं बढ़ाया जाता, अपितु भ्रामक और झूठे मुद्दे उछालकर सरकारों को अस्थिर करने का कुचक्र किया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं पर हल्ला बोला जाता है. इस शैली में सत्य पर, तथ्य पर अथवा तर्क पर कोई बात नहीं होती केवल धुंध फैलाई जाती है. ऐसी धुंध कि जिसमें कुछ भी साफ न दिखे, जन सामान्य भ्रमित होकर सड़कों पर आ जाये और सत्ता भयभीत होकर सिमट जाय.

2014 में केन्द्रीय सत्ता से बाहर होने के बाद कॉंग्रेस ने जितने भी मुद्दे उठाये गये हैं वे सभी नकारात्मक रहे हैं. उनके निशाने पर पहले प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी थे. उनको लक्ष्य करके चौकीदार चोर जैसे नारे उछाले गये. सीएए को मुद्दा बनाकर देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास हुआ. किसान आँदोलन के बहाने गाँवों में असंतोष भड़काने का प्रयास हुआ. ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछालकर देश में सामाजिक अलगाव की रेखा गहरी की गई. लेकिन मोदीजी बिना विचलित हुये भारत राष्ट्र को सशक्त बनाने के अभियान में जुटे रहे. वे विकसित देशों की पंक्ति में भारत को अग्रणी बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यह मोदीजी की संकल्पशीलता और सकारात्मक चिंतन का ही परिणाम था कि विपक्ष द्वारा उछाले गये नकारात्मक मुद्दों का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और मोदीजी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी. 2024 के चुनाव परिणाम के बाद कॉंग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपनी नकारात्मक रणनीति को ही विस्तार देकर अधिक आक्रामक बनाया और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले तेज किये गये. ये हमले ईडी, सीबीआई, एनआईए पर हुये. सेना और न्यायालय तक को नहीं छोड़ा गया. अब चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम पर अधिक फोकस किया जा रहा है. पहले ईवीएम मशीन को हैक करने का शोर मचाया गया था. और अब मतदाता सूची हाथ में लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का शोर है. कॉंग्रेस और राहुल गांधी अपनी शिकायत लेकर सिधे चुनाव आयोग नहीं पहुँचे, आयोग ने बुलाया प्रमाण माँगे फिर भी नहीं पहुँचे. लेकिन सड़क से संसद तक अपनी आवाज तेज और तीखी करते रहे.

मतदाता सूची तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है. मतदाता सूची बनाने अथवा चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का काम चुनाव आयोग के निर्देशन में तो होता है लेकिन इसके लिये चुनाव आयोग के पास कोई अपना स्टॉफ नहीं होता. यह काम राज्यों में काम करने वाला प्रशासन तंत्र करता है. देश में कुल 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं. प्रशासनिक दृष्टि से इन्हें कुल 780 जिला केन्द्रों में विभाजित किया गया है. जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर होता है. चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और सभी राज्यों की राजधानी में राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय तो होते हैं. पर उनमें इतना स्टॉफ नहीं होता कि यह वे स्वयं यह काम कर सकें. चुनाव आयोग केवल नीति निर्देशिका अर्थात गाइड लाइन तैयार करता है. जो देश के सभी कलेक्टरों को भेजी जाती है. उसके अनुसार चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है. संबंधित सभी जिला कलेक्टर अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी भी माने जाते हैं. वे ही मतदाता सूची बनाने केलिये घर घर जाकर सर्वे करने अथवा मतदान प्रक्रिया पूरी करने के काम का समन्वय करते हैं. इसमें शिक्षक और पटवारी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक पूरा प्रशासनिक अमला लगता है.

तानाशाहों के युद्धोमांद से क्यों डरता है यूरोप

डॉ . ब्रह्मदीप अलूने
विदेशी मामलों के जानकार

यूरोप बखूबी जानता है कि तानाशाही सिर्फ शासन प्रणाली नहीं होती है, यह युद्ध, शरणार्थी संकट, नरसंहार और लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन का दूसरा नाम है . रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लाखों लोग यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में जा रहे है और इससे बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया है . यूरोप तानाशाही से इसलिए डरता है क्योंकि उसकी सामूहिक स्मृति में हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन के शासन की भयावह छाया अब भी मौजूद है . पुतिन की आक्रामक नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती है . यह यूरोप के लिए वह केवल वर्तमान चुनौती नहींए बल्कि अपने अतीत की डरावनी यादों की पुनरावृत्ति भी है . इसीलिए यूरोप बार-बार अमेरिका और नाटो की ओर देखता है .

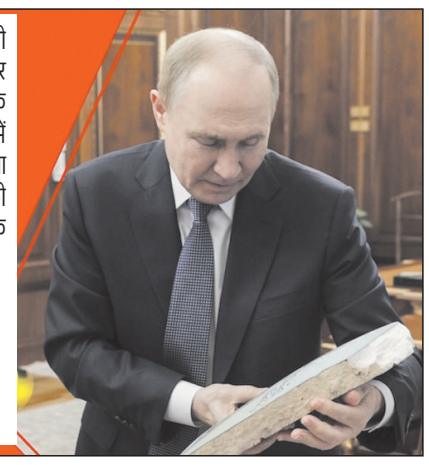

यूरोप का राजनीतिक इतिहास तानाशाही और लोकतंत्र के बीच निरंतर संघर्ष का है. 1917 की रूसी क्रांति, 1920-30 के दशक का फासीवाद और 1933 के बाद का नाज़ीवाद ऐसे दंश है जिससे यूरोप अब भी कराहता है और दहशत में रहता है. यह दौर यूरोप को उस अंधकार में ले गया था जहां से निकलने में दशकों लग गए. द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, यहूदियों का सामूहिक संहार और करोड़ों लोगों की मौत ने यूरोप को सिखाया कि तानाशाही सत्ता पर पूर्ण नियन्त्रण करके युद्दोंमाद को बढ़ाती है तथा इसका दूरगामी परिणाम सभ्यता का विनाश तक हो सकता है. 1917 की रूसी क्रांति ने यूरोप को पहली बार व्यावहारिक साम्यवादी तानाशाही से परिचित कराया. व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और एक सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना की. इस क्रांति ने पूरे यूरोप में यह आशंका फैलाई कि वैचारिक उथल-पुथल राजनीतिक असंतुलन को जन्म देकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म कर सकती है.

रुसी क्रांति के दो साल बाद, 1919 मेंए इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने फासीवादी पार्टी की स्थापना की. प्राचीन रोम के फासिस प्रतीक पर आधारित यह विचारधारा शक्ति और राष्ट्रवाद के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती थी. इटली का यह प्रयोग जल्द ही स्पेन और अन्य लैटिन देशों तक फैल गया. 1923 में स्पेन में जनरल मिगुएल प्रिमो डी रिवेरा ने लोकतंत्र को खत्म कर मार्शल लॉ लागू किया. आगे चलकर 1936 में फ्रांसिस्को फ्रैंको ने जर्मनी और इटली की मदद से स्पेन में फासीवादी फशासन स्थापित किया. यह यूरोप के लिए गहरी चेतावनी थी कि लोकतंत्र कितनी जल्दी तानाशाही में बदल सकता है.

यूरोप की सबसे भयावह तानाशाही एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में विकसित हुई. नाज़ी प्रतीक स्वस्तिक ने केवल राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि नस्लीय वर्चस्व और सामूहिक संहार की वैचारिक योजना को जन्म दिया. हिटलर की विकृत नस्लवादी विचारधारा के परिणामस्वरूप यूरोप की धरती पर ऐसे मृत्यु शिविर खड़े किए गएए जहां यहूदी, जिप्सी, विकलांग, राजनीतिक विरोधी और लाखों निर्दोष लोग बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए. हिटलर और फासीवादी गठबंधन की आक्रामकता ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दियाएजो मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष बना. इस युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए. अकेले यूरोप में 2 करोड़ लोगों की जान गई. नाज़ी नरसंहार शिविरों में 60 लाख यहूदियों सहित लाखों अन्य निर्दोषों का योजनागत तरीके से संहार हुआ. इससे जर्मनी स्वयं भी बर्बाद हो गया.

1945 के बाद यूरोप ने तानाशाही से दूर रहने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया जिससे राजनीतिक व आर्थिक साझेदारी युद्धों और तानाशाही की पुनरावृत्ति रुक सके. इसके साथ ही विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं ने नागरिक स्वतंत्रताओं को लोकतंत्र का मूल आधार बनाया. आज यूरोप की सबसे बड़ी चिंता रूस है. व्लादिमीर पुतिन की नीतियों में यूरोप को 20वीं शताब्दी की तानाशाही की गूंज सुनाई देती है. पुतिन, जोसेफ स्टालिन की राह पर है. स्टालिन खुद को देशभक्त और मसीहा नेता के तौर पर प्रचारित करते थे तथा लोकप्रियता की आड़ में विरोधियों को मरवा देते थे. स्टालिन ने लाखों लोगों को मरवा दिया था. पुतिन भी अपने विरोधियों का वहीं हश्र कर रहे है. पुतिन की कार्यशैली और नीतियों का विरोध करने वालों तथा रूस में असंतोष की आवाज़ उठाने वाले विपक्ष को लगभग ख़त्म कर दिया गया है. पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को कैद किया और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से क़ानूनी या बलपूर्वक रोक दिया.

पुतिन का इतना खौफहै कि पचास करोड़ यूरोपीयएतीस करोड़ अमेरिकियों से चौदह करोड़ रूसियों के ख़िलाफ सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं. यूरोप एक ऐसा भूभाग है जिसकी सीमाएं ज्यादातर ऐतिहासिक समझौते, युद्धों और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाओं के परिणामस्वरूप बनीं. यह सीमाएं राजनीतिक और सैन्य संतुलन की उपज हैं. यही कारण है कि यूरोपीय समाज बार.बार शक्ति संतुलन और राजनीतिक स्थिरता को लेकर असुरक्षित महसूस करता रहा है.

रूस एक अंतरमहाद्वीपीय राष्ट्र है, जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है. हालांकि इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय ही माना जाता है. यूरोप का पूंजीवाद रुसी प्रभाव से आशंकित रहा है और उसे रूस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजदीकियां भी मंजूर नहीं है. यूरोप ने हजारों मील की दूरी पर स्थित अमेरिका को अपना सुरक्षा कवच बनाने का जोखिम उठाया था. जैसे ही ट्रम्प ने साम्यवाद और पूंजीवाद की राजनीतिक दूरियों को आर्थिक संरक्षणवाद की नीति के आगे बौना साबित करने की कोशिश की तो इसकी दहशत से यूरोप कंपकंपाने लगा है. रूस के साथ बेहतर सम्बन्ध प्रबंधित करने का ट्रम्प के तरीके को जेंलेंसकी के सार्वजनिक अपमान की कोशिशों के तौर देखा गया है जिससे यूरोप में गुस्सा और चिंताएं है.

पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन की भू रणनीतिक स्थिति रूस और यूरोप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसकी सीमा उत्तर में बेलारूसएपश्चिम में पोलैंडएस्लोवाकिया और हंगरी से लगती है. जबकि दक्षिण.पश्चिम में रोमानिया और माल्दोवा से लगती हैएयूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है. 2014 में यूक्रेन युद्ध का मैदान बन गया जब रूस ने क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया और देश के दक्षिण.पूर्व में डोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों को हथियार और सहायता देना शुरू कर दिया. रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार था जब किसी यूरोपीय राज्य ने किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्ज़ा किया हो. ट्रम्प के पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की बहाली के लिए प्रतिबद्धता दिखाता रहा और उसने रूस द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए अन्य क्षेत्रों पर रूस के दावों को मान्यता नहीं दी. ट्रम्प अमेरिका के पुराने रुख से हट गए है. यह यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का संकट समझा जा रहा है. यूरोप की सुरक्षा में अमेरिकी सेना का अहम योगदान है. यूरोप पर अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की स्थिति में बदलाव से ना केवल रूस की आक्रामकता बढ़ेगी, बल्कि यूरोपीय गठबंधन भी कमजोर पड़ सकते हैं.

व्यंग्य

भैंस पर महा अभियोग

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

पावस सत्र के दौरान आदरणीय सभापति के समक्ष विपक्षी सदस्यों ने भैंसो के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव पेश किया और महाभियोग पर सदन में तुरंत बहस करा कर भैसों पर महाभियोग चलाने का अनुरोध किया . विपक्षी सदस्यों ने सभापति जी से आग्रह किया लोकहित के इस प्रस्ताव पर तत्काल बहस करा ली जाए लोकहित के इस प्रस्ताव पर बहस के लिए सभापति जी ने सत्ता पक्ष के प्रबल विरोध के वाबजूद दो दिन बाद का समय निर्धारित कर दिया .

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सभापति जी इस महाभियोग प्रस्ताव में कोई लोकहित नहीं है, बल्कि इस प्रस्ताव से पशु क्रूरता को बढ़ावा मिलेगा . परंतु पहले से सत्ता पक्ष से ख़ार खाए बैठे सभापति जी ने उनकी एक नहीं सुनी और अपना पशु प्रेम प्रदर्शित करते हुए प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया . महाभियोग के लिए सोमवार को महा बहस होनी थी . सम्पूर्ण भैंसखेड़ी में यह खबर बरसात की बाढ़ की तरह चारों तरफ फैल गई . भैंसाखेड़ी मैं इसको लेकर भैंसासुरों में आक्रोश फैल गया . इस आक्रोश को सत्ताधारी दल के सदस्यों ने अपने आंदोलन के पिटारे से निकाला था . भैंसाखेड़ी से विधान कक्ष तक जुलूस निकाला गया . जिसमें नारे लग रहे थे नहीं सहेंगे -नहीं सहेंगे . भैंसों पर अत्याचार नहीं सहेंगे . पाड़े-पड़िया करें पुकार नहीं सहेंगे, ये अनाचार . भैंसों पर बंद करो यह सितम- वरना दूध देना बंद करेंगे हम . भैंस एकता जिंदाबाद-जिंदाबाद .

महाभियोग पर विधानकक्ष में बहस के दिन भवन के अंदर -बाहर खचाखच भीड़ थी . बाहर सैकडों भैंसों की रैली थी . भैंसों की रैली स्थल का नज़ारा ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक था . वे एक साथ संवेत गान में भारी आवाज में उँ . .आं, अम . . आं . .आं कर रहीं थीं .विधान परिसर के बाहर का नजारा देखते ही बनता था . वहां सड़क पर चारों तरफ हरे-खाकी रंग मिश्रित गोबर ही गोबर पड़ा था . भैंस मूत्र के नाले जैसे बह रहे थे . वहां पड़े गोबर में कुछ तमाशबीन और जनप्रतिनिधि भी फिसल कर लटा-लोट हो गए थे .

जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह खबर लगी, तो वह भी अपने-अपने कैमरा लेकर घटना स्थल पर जा पहुंचे . वहां पहले उन्होंने भैंसों का सामुहिक वीडियो शूट किया . इसके बाद वह भैंसों के पार्श्व में पहुंच कर जब वीडियो बनाने लगे तो एक भैंस ने जो अपनी लंबी कोड़े जैसी पूंछ जो घुमा कर मारी तो वो जा कर कैमरा मेन के चेहरे पर जा कर सटाक से पड़ी रिपोर्टर और कैमरा मैन वहां बह रहे भैंसों के मूत्र से फिसल कर गोबर पर जा गिरे . पीछे से आवाज आई . भैसों के प्राइवेट पार्ट के पीछे का वीडियो बनाने का नतीजा देख लिया . भैंसों की भी निजता है .विधान कक्ष में अंदर भी भारी गहमा गहमी थी . पत्रकार दीर्घा खचाखच भरी महिला और पुरुष रिपोर्टर अभूतपूर्व कवरेज को दो चार होने को थे . कोई कैमरा सेट कर रहा था तो कोई मोबाइल को सेट कर रहा था . पीछे से आवाज आई एक जरूरी सूचना, किसी भी पत्रकारों बंधु और पत्रकार लेडी को वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है . इसके अलावा थर्ड जेंडर को भी पिक्चर विलक की अनुमति नहीं है . कृपया व्यवस्था बनाए रखें . पीछे से कोई बोला हम तो उच्च और निम्न सदन का ही अनुसरण कर रहे हैं .मुर्दाबाद, मुर्दाबाद . आसंदी पर बैठे पीठासीन अधिकारी ने अपना करम ठोक कर बोला मैं कहाँ इन मुर्दों के बीच आ बैठा . कुछ सुनते ही नहीं है . तभी उनके दिमाग का बल्ब चमका, आसंदी से बैठे व्यक्ति ने इशारे से मार्शल को बुला कर अपनी छोटी उंगली का इशारा किया . वह व्यक्ति उनके कान में फुसफुसा कर कहा पहले वाले दोनों श्रीमान आधा घंटे से वहाँ अंदर बैठे हैं . आप थोड़ा रोक लो . इस सूचना के बाद गार्ड ने देखा कि एक युवक चेतावनी के बाद भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था . गार्ड उस युवक के पास पहुंचा और बोला आपने सुना नहीं यहां वीडियो बनाना मना है . इस पर युवक बोला वह सूचना तो पत्रकारों के लिए है . हम वो नहीं हैं .गार्ड ने पूछा फिर आप कौन हैं . युवक बोला हम प्योर आदमी है . हमारे साथ किसी तरह की कोई पूंछ नहीं लगी है . न पत्रकार की न कोई और . ., हम प्योर सरकार बनाने वाले लोग हैं, जिसे कहते हैं मतदाता,और इस रिश्ते से तो हम-तुम हुए भाई- भाई .भला बताओ क्या कोई भाई से ऐसा दुश्मनों जैसा व्यवहार करता सकता है .वह युवक से बोला -है प्योर सरकार बनाने वाले मेरी नोकरी की लाज बचा ले वरना साहब फायर कर देंगे . वैसे भी मैं ले देकर डेली वेज पर लगा हूं . सदन में भैंस के महाअभियोग पर गर्मागर्म बहस हो रही थी . सदन का दृश्य किसी सरकारी स्कूल के क्लास रूम जैसा लग रहा था . सभापति सदस्यों से हाथ जोड़ कर अपील कर रहे थे . भाईयों अपनी सीट ग्रहण कीजिए . आपको समझाते हुए मेरी डेस्क पर का लकड़ी का हथौड़ा टूट गया है . चुप हो जाइए . आसंदी पर बैठे सभापति व्यक्ति के गिड़गिड़ाने के बाद सदस्यों का शोर गुल नारे बाजी बंद हुई तो सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई . सत्ता पक्ष के प्रमुख ने विपक्ष के आरोप का उत्तर देते हुए कहा कि सभापति महोदय मेरा अनुरोध है कि भैंस पर महा अभियोग का प्रस्ताव आग्राह्य किया जाए . यदि ऐसा किया जाता है तो भैंस जैसे शांत पशु पर यह प्रस्ताव अत्याचार होगा . सभापति जी यदि इसके लिए कोई दोषी है तो वह विपक्ष है . विपक्ष भैंसों के पास जा कर बीन बजा कर अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन किया है .

सभापति जी यह बड़ा से बड़ा मूर्खानंद भी सदियों से यह जानता है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता . यदि ऐसा किया जाता है तो यह भैंसों का अपमान है . इस घटना के लिए बीन बजाने वाले विपक्ष को भैंसों से सदन में और सदन के बाहर राजधानी के तबेलों में जा कर माफी मांगनी चाहिए, तभी भैंसों को न्याय मिलेगा . सभापति जी यदि ऐसा नहीं हुआ तो जान लीजिए कि यमराज के वाहन की भैंसे रिश्ते में बहनें लगती हैं और यदि आदरणीय यमराज महाराज के वाहन को इस घटना को पता चल गया और वह यमराज सर को लेकर यहां आ गए तो सोच लो फिर क्या होगा ?

यह सुनते ही सभापति अपनी आसंदी से उछल कर खड़े हो गए और विपक्ष की तरफ हाथ जोड़ कर बोले भैया खुद ही यह महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लो हमारी और तुम्हारी जान को क्यों दांव पर लगा रहे हो ?

पूरे मामले पर विचार करने के बाद मोटे पेट वाले लहिम शहीम विपक्ष के नेता ने प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा हम इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं और पशुप्रेमी होने के नाते भैंसों से माफी मांगते हैं . तभी सदन तालियों से गूंज उठा . और फिर सदन में बीन की आवाज गूंज उठी . सदन के बाहर बैठीं भैंस भी खुशी से झूम कर समवेत स्वर में रंभाने और उनके गलों में लटकी घंटियां टनटनाने लगीं .

श्याम यादव
(स्वतंत्र पत्रकार)

बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इस बारे में अभी कुछ भी कयास लगाना मुश्किल है। क्योंकि, इस बार विपक्ष ने जिस ताकत से चुनाव आयोग पर हमले किए, उससे माहौल कुछ अलग दिशा में जाने का संकेत दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा भी अलग रंग दिखा रही है। उनकी यात्रा में जिस तरह भीड़ जुट रही है, उससे यह कहा जा सकता है की स्थिति का आकलन आसान नहीं है।

बिहार में राहुल की वोट अधिकार यात्रा कारगर होगी ?

अपनी दो यात्राओं से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 55से 99 सीट तक पहुंचाने वाले राहुल गाँधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. पहले निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा राहुल गाँधी ने अकेले निकली थी. जबकि बिहार क़ी वोट अधिकार यात्रा केवल अकेले राहुल गाँधी क़ी नहीं है इस यात्रा में विपक्षी दल खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव क़ी भी भागेदारी है . इस यात्रा का कितना असर बिहार क़े आगामी चुनाव पर पडेगा यह देखने वाली बात होगी. लेकिन बिहार क़ी नितीश कुमार क़ी सरकार क़े लिए ये खतरे क़ी घंटी मानी का रही है .

लोकसभा चुनावों से पूर्व निकाली गई अपनी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा क़े परिणामों को एक अस्त्र मान कर राहुल गाँधी बिहार में भी इसे आजमाने निकले हैं. बिहार में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल क़े साथ एक जुट हो कर इस बार सत्ता परिवर्तन क़े प्रयास में है और इसके लिए खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है. राहुल गाँधी वोट अधिकार यात्रा निकाल कर जनता को यह अहसास कराने की कोशिश में हैं कि बिहार क़ी अगुआई में ही उस वोट चोरी को रोका जा सकता है. जो भाजपा

सरकार द्वारा की जा रही है. इस यात्रा में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव क़ी भागीदारी और उनकी वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार सरकार को उखाड़ फैकने क़े आव्हान ने बिहार क़ी जनता क़े मन में सरकार विरोधी भावना भरने का ही काम किया है .

क्या राहुल गाँधी की इस वोट अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ आगामी चुनाव में वोटों में परिवर्तित हो पाएगी ?यह सौ टके का सवाल है. जिसका जवाब वक़्त क़े अलावा किसी क़े पास नहीं है. राहुल गांधी अपनी इस वोट अधिकार यात्रा को जिसे वे जनता क़े वोट देने क़े अधिकार को छीने जाने का मुद्दा बना कर जनता क़े सामने रख रहे है.राहुल जनता को यह अहसास करा रहे है कि उनको संविधान ने जो वोट का अधिकार दिया है उसकी चोरी की जा रही है . सवाल यही है कि राहुल इस मुद्दे को विधानसभा चुनावों तक कायम रख पाएंगे? इन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं है.

लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गाँधी क़े इन प्रयासों की कोई न कोई काट भाजपा जरूर निकलेगी . उस स्थिति में कांग्रेस और राहुल का अगला कदम परिस्थितियों का निर्धारण करेगा.